LOK SABHA

Friday, August 11, 1978/Sravana 20, 1900 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Decision to take over Distribution of Essential Commodities

+

*385. SHRI GANANATH PRADHAN:

SHRI KANWAR LAL GUPTA:

Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to take over the distribution of essential commodities into its own hand;

(b) whether the essential commodities will be sold through fair price shops throughout the country; and

(c) if so, the details threeof and the names of the items, to be sold as 'essential commodities' through fair price shops?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (ग) मंत्रालय ने राज्य सरकारों, सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयो तथा योजना आयोग के परामर्श से ग्राम खपत की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की एक योजना को अंतिम रूप दिया है । यह योजना मंत्रिमडल के विचाराधीन है ।

श्री गणनाथ प्रधान : अध्यक्ष महोदय, सिविल सप्लाइज मिनिस्ट्री ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को कुछ प्रोपोजल्स मास कन्जम्पशन की एसेंशियल कामोडिटीज जैसे सीरियल्स, पल्सेज और एडिबिल आयल्स के बारे में भेजे थे लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उन प्रोपोजल्स को मान नहीं रही है, ऐसा बताया जा रहा है । इसके बारे म स्टेटमेंट में कुछ नहीं है । इस के अलावा जनता सरकार जब पावर में आई तो लेबर बेल्ट, हिली एरियाज और देहाती इलाके जो हैं, उनमें फेयर-प्राइस शाप्स खोलने के लिए कहा था, जोकि अभी तक नहीं खुली हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या सोच रही है और जो दाल और एडिबिल आयल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है और जो इन्फीरियर क्वालिटी का गेहूं और चावल लोगों को फेयर प्राइस शाप्स से दिया जा रहा है, उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है । अब तो शूगर भी डी-कन्ट्रोल हो गई है, इसलिए फेयर प्राइस शाप्स के बारे में वह क्या करने जा रही है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जैसा कि उत्तर के अन्दर कहा है "कि यह सारी योजना कैबिनट के विचाराधीन है लेकिन आप ने जो बताया है, इस सारी योजना के अन्दर उसका पूरा ध्यान रखा गया है और कोई भी क्षेत्र हो चाहे वह पहाड़ों क अन्दर हो या शहरों के अन्दर हो, जिन वस्तुओं को वितरण प्रणाली के अन्दर कवर करना है. उन सब का मूल्य सब जगह समान होगा, इस बात का ध्यान रखा गया है । उन वस्तुओं के लिये जिन के बारे में शिकायत आती है कि वे ठीक प्रकार की नहीं दी जा रहीं हैं, तुरन्त जो भी सम्बन्धित कार्पोरेशन्स हैं या मंत्रालय है या विभाग है, उनसे कहा जाता है कि वे चीजें ठीक प्रकार की मिलें, स्वच्छ मिलें । इस चीज पर पूरा ध्यान दिया जाता है कि लोगों को चीजें ठीक प्रकार की मिलें ।

श्री गणनाथ प्रधान : सरकार के पास बहुत ज्यादा फारेन एक्सचेन्ज है और मंत्री जी ने यह बताया था कि इस को ले कर वे उन चीजों पर खर्च करेंगे जिनका कमी है और जो एसेंशियल कामोडिटीज हैं और उन को खरीद कर काओपरेटिव के माध्यम से और दूसरे जो सरकार के माध्यम हैं, उनके द्वारा उसका डिस्ट्री-ब्यूशन होगा । अभी तक उस बारे में सरकार ने क्या किया है, यह मैं जानना चाहता हूं और दूसरी बात यह है कि जिन चीजों का प्राडक्शन

कम है, उनके बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अन्दर इस बात का ध्यान रखा गया है कि दो हजार की आबादी को आधार बना कर फेयर प्राइस शाप्स का एक जाल सा बिछाया जाए और इस के अन्दर भी रिजिडिटी नहीं होगी । पंचायत हेडक्वार्टर्स पर कम से कम यह हो, ऐसा हम चाहते हैं और अगर यह देखा गया कि गांव बहुत दूर दूर तक बिखरे पड़े हैं, तो भी लोगों को फेयर प्राइस दुकान पर सामान मिल जाए, इसके लिए दो हजार की आबादी को हमने जो अपना आधार माना है उसको कुछ शिथिल किया जा सकता है ।

शक्कर के बारे में आपने कहा । शक्कर के बारे में भी स्पष्ट निणय लिया गया है कि शक्कर सभी को दो रुपये पिचहत्तर पैसे प्रति किलो पर दी जाए और इसका मूल्य नहीं बढ़ने दिया जाए ।

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, आज से करीब 9–10 महीने पहले हमारे माननीय मंत्री, धारिया जी ने कहा था कि

"I have become a warning Minister; I will not continue as a warning Minister. I will see that specific steps are taken to see that essential commodities are provided to every person at reasonable price, good quality...."

अध्यक्ष महोदय, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो योजना आपने बनायी है, इसकी मोटी मोटी तफसील क्या है और कब से यह लागू हो रही है ? क्या बिलो पावर्टी लाइन के लोगों को यह गारन्टी देंगे कि इस प्राइस पर, रीजनेबल प्राइस पर, एसेंशल कमोडिटीज उनको देते रहेंगे ? यह जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं—जैसे तेल, दाल, चावल आदि क्या उनको रीजनेबल प्राइस पर मिलती रहेंगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में सरकार की नीति बिलकुल स्पष्ट है और सरकार यह मानती है कि जनता की जरूरत की चीजें उसको अच्छे दाम पर मिलें । (व्यवधान) दिन्दी का प्रश्न है, मैं हिन्दी में जवाब दे रहा हूं । अच्छे दाम से मेरा मतलब है रीजनेबल प्राइस पर मिलती रहें ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I do not mind if you speak in English.

श्री मोहन धारिया : ये चीजें उनको मुनासिब दाम पर मिलें, यह हमारी नीति है । जैसा कि मैंने आश्वासन दिया था कि इसके लिए हम एक प्रोडक्शन-कम डिस्ट्रिब्यूशन स्कीम तयार करेंगे उसके अनुसार मेरे मंत्रालय ने प्लानिंग कमीशन अलग-अलग मंत्रालयों और स्टेट गवनमेंट्स के साथ बातचीत करने के बाद एक स्कीम तयार की है और वह स्कीम केबिनट के सामने विचाराधीन है । जब तक उस पर आखिरी फैसला नहीं हो जाता तब तक उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा । हमारा यह ख्याल जरूर है कि जो जरूरत की चीजें ह उनको लेकर, यह देखा जाए कि उनका कैसे उत्पादन हो, कसे वितरण हो और कैसे देहात और शहर के लोगों को वे दे सकें । इस सब के बारे में हम ने विचार किया है ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA: My question was....

MR. SPEAKER: You cannot have a debate.

SHRI MOHAN DHARIA: May I finish what I wanted to say?

यह स्कीम बनी है और मैं यह जरूर आश्वासन देना चाहता हूं कि यह सरकार अपनी जिम्मेदारी मानती है कि जनता की जरूरत की चीजें जनता को मुनासिब दामों पर मिलें । उनको मुनासिब दामो पर चीजें देना सरकार का कर्त्तव्य है ।

SHRI CHITTA BASU: I congratulate the hon. Minister for the announcement of the policy. But may I know from the hon. Minister whether he has taken into account two very important elements in the matter—production of the mass consumption items and distribution by the public distribution system, namely, element of subsidy and fiscal control over consumption items at the source level. Unless the scheme takes into account these important and vital elements, the scheme is not likely to be sucessful May I know from the Minister in this context whether he has discussed these points with his Cabinet colleagues and whether a firm decision has been taken on it and approved by the Planning Commission, particularly regarding the element of subsidy and the question of physical control over the items of mass consumption at the production or sound level?

SHRI MOHAN DHARIA: Even under the existing distribution system the House may be aware that there is an element of subsidy. Take for instance foodgrains. There is an element of subsidy of the order of Rs. 450 crores or more. Naturally for any distribution system, subsidy element becomes a must. Simultaneously, it is not necessarily taking over the trade but it is the physical control and proper market intervention to maintain the price which becomes a must. Both these things are taken into consideration.

श्री चन्द्र शेखर सिंह मंत्री महोदय ने कहा है कि दो हजार की आबादी पर इस तरह की सस्ती दूकानें खोली जाएंगी और उनका स्तर न्याय पंचायत का स्तर होगा । मैं पूछना चाहता हूं क्या आप इस बात को ख्याल में रखेंगे कि लोगों को मुनासिब कीमत पर गल्ला दिया जाए या राशन दिया जाए । मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि यह जो मुनासिब शब्द आपने कहा है इसका आधार क्या है और मुनासिब कीमत निर्धारित करते समय क्या इस बात की कोशिश की जाएगी कि जो सत्तर प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे निवास करते हैं उनकी क्रय शक्ति को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब कीमत तय की जाए ?

अभी जो सस्ते गल्ले की दूकानें हैं, सस्ती राशन की दूकानें हैं ये कितनी हैं देश में और दो हजार की जनसंख्या के आधार पर इनको खोला गया है या इससे ज्यादा की संख्या पर, और अगर ज्यादा की संख्या पर खोला गया है तो अगर दो हजार के आधार पर इनको खोलना है तो कितनी और दूकानें आपको खोलनी पड़ेंगी और ये कब तक खुल जाएंगी ?

श्री मोहन धारिया : जिस वक्त मुनासिब कीमत तय होती है तो जरूर हमारे मुल्क में जो गरीब लोग हैं उनकी परिस्थिति को ख्याल में ले कर ही यह काम किया जाता है और किया जाएगा ।

हमारे देश में आज लगभग 2 लाख 40 हजार फेयर प्राइस शाप्स हैं जिन में से 1 लाख 80 हजार निजी क्षेत्र की हैं और 60 हजार कोआपरेटिव सोसाइटीज के क्षेत्र में हैं । अगर दो हजार की आबादी के लिए एक शाप्स देनी है तो लगभग 3 लाख 20 हजार हमें खोलनी पड़ेंगी । उनके साथ ऐसे भी कुछ गांव हैं जिन की आबादी आठ सौ या एक हजार की है और वे काफी दूर हैं । ऐसे गांवों में भी हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन सैंटर देना होगा । इन सभी बातों को ध्यान में रख कर मैंने स्कीम तैयार की है ।

M/s. Auto Pins (I) Regd.

+

*387. SHRI R. L. P. VERMA:
SHRI K. LAKKAPPA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that M/s. Auto Pins (I) Regd. its associates, Branch offices and dealers all over the country are under investigation for indulging in black money sales;

(b) If so, whether Government will lay on the Table of the House a copy of the findings thereof;

(c) what action Department of Banking propose to take in respect of freezing the credit limits to those companies who enjoy credit limits from Nationalised Banks of more than a crore of rupees; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to check large-scale exploitation of public funds for personal ends at the cost of the Exchequer with immense volume of revenue being lost by the Centre and the States, and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). The premises of M/s. Auto Pins (India) Regd. and its partners were raided by the Income-tax authorities and the Enforcement Directorate (Foreign Exchange Regulation Act). Arising out of search and seizure operations by the income-tax authorities, an order under Section 132 (5) of the Income-tax Act has been passed estimating the undisclosed income of the firm for the assessment year 1976-77 in a summary manner. Further, arising out of searches by the Enforcement Directorate show cause notices were served on the company and persons concerned. These cases have been heard and adjudication orders will be issued shortly. The prosecution aspect of these cases will be examined on completion of departmental adjudication.